



## गगि वर्करस राइट्स

### प्रलिमिंस के लयि:

गगि इकॉनमी, असंगठति श्रमकि सामाजकि सुरक्षा अधनियिम 2008, सर्वोच्च न्यायालय, हाई-स्पीड इंटरनेट, कोवडि-19 महामारी, पेंशन योजनाएँ, डजिटल डविाइड, सामाजकि सुरक्षा ।

### मेन्स के लयि:

भारत में गगि अर्थव्यवस्था के वकिस चालक, भारत में गगि श्रमकिों से संबंघति मुद्दे ।

## चर्चा में क्यों?

20 सतिंबर, 2021 को इंडियन फेडरेशन ऑफ एप-बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्करस ने [गगि वर्करस](#) की ओर से [सर्वोच्च न्यायालय](#) में एक जनहति याचकिा दायर कर मांग की कर्केदर सरकार महामारी से प्रभावति श्रमकिों को सहायता प्रदान करे ।

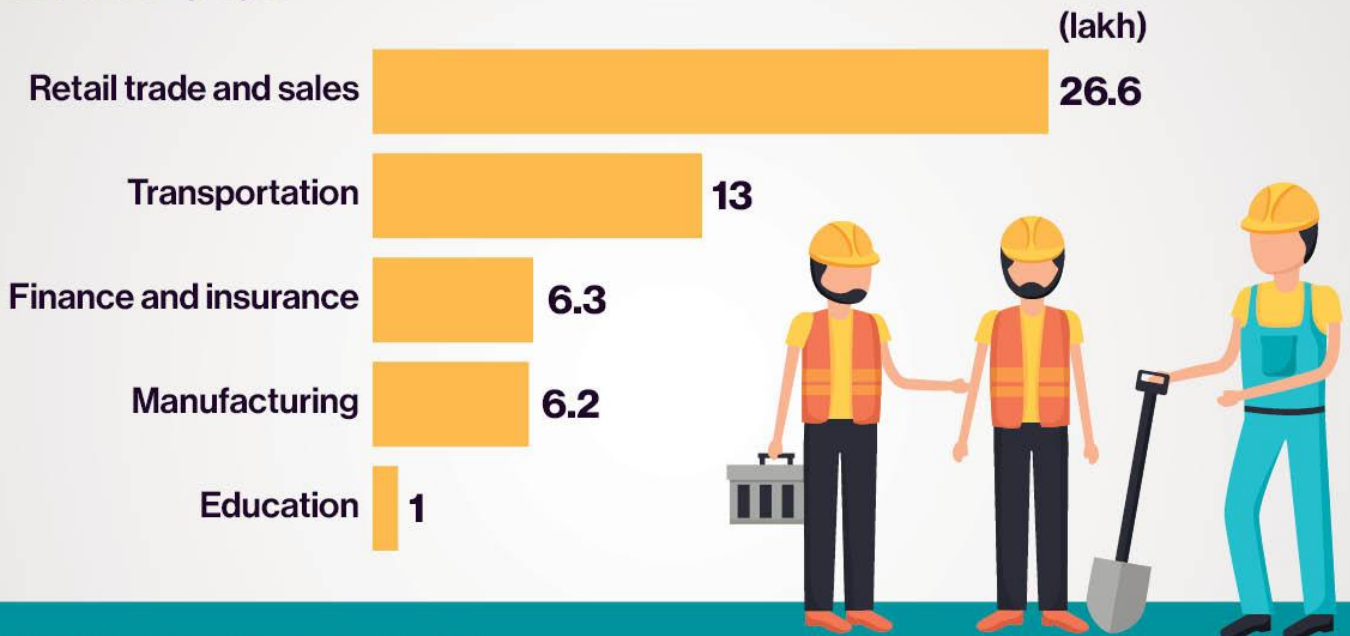
- याचकिा में 'गगि वर्करस' और 'प्लेटफॉर्म वर्करस' को 'असंगठति श्रमकि' घोषति करने की मांग की गई है ताककिे [असंगठति श्रमकि सामाजकि सुरक्षा अधनियिम, 2008](#) के दायरे में आ सकें

## गगि इकॉनमी:

- परचिय:
  - [गगि इकॉनमी](#) एक मुक्त बाज़ार प्रणाली है जसिमें पारंपरकि पूरणकालकि रोज़गार की बजाय अस्थायी रोज़गार का प्रचलन होता है और संगठन अल्पकालकि अनुबंधों के लयि स्वतंत्र श्रमकिों के साथ अनुबंध करते हैं ।
  - [गगि वर्कर](#): गगि वर्कर को एक ऐसे व्यक्ती के रूप में परभाषति कयिा गया है, जो पारंपरकि नयौक़ता-कर्मचारी संबंधों के बाहर काम करता है या कार्य व्यवस्था में भाग लेता है और ऐसी गतविधियों से आय अर्जति करता है ।

# GIG WORKFORCE IN INDIA

NITI Aayog, in its report, India's Booming Gig and Platform Economy, said that gig workforce in India is expanding. As of 2019-20, here's what the following sectors employed:



NITI Aayog report stated:



■ भारत में गिग इकॉनमी के विकास चालक:

- इंटरनेट और मोबाइल प्रौद्योगिकी का उदय: स्मार्टफोन को व्यापक रूप से अपनाने और **हाई-स्पीड इंटरनेट** की उपलब्धता ने श्रमिकों एवं व्यवसायों के लिये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ना आसान बना दिया है, जिससे गिग इकॉनमी के विकास में आसानी हुई है।

- **आर्थिक उदारीकरण:** भारत सरकार की आर्थिक उदारीकरण नीतियों ने प्रतस्पर्द्धा और अधिक खुले बाज़ार को बढ़ावा दिया है, जिसने गगि अर्थव्यवस्था के विकास को प्रोत्साहित किया है।
- **वभिन्न प्रकार के काम की बढ़ती मांग:** गगि अर्थव्यवस्था भारतीय श्रमिकों के लिये विशेष रूप से आकर्षक है, ऐसे में यह लचीली कार्य व्यवस्था की तलाश कर रहे लोगों को व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को संतुलित करने की सुविधा प्रदान करती है।
- **जनसांख्यिकीय कारक:** गगि अर्थव्यवस्था युवा, शक्ति और महत्वाकांक्षी भारतीयों की बड़ी एवं बढ़ती संख्या से भी प्रेरित है, ये वो लोग हैं जो अतिरिक्त आय सृजन के साथ अपनी आजीविका में सुधार करना चाहते हैं।
- **चीन के संदर्भ में:**
  - चीन में सार्वजनिक वमिर्श के बीच फूड डलिविरी प्लेटफॉर्म को लेकर सरकार द्वारा जाँच में तेज़ी लाई गई है। यह मामला विशेष रूप से **कोविड -19 महामारी** का उत्पत्त केंद्र माने जाने वाले वुहान से संबंधित था जहाँ सामाजिक वमिर्श स्पष्ट रूप से डलिविरी वर्कर्स के पक्ष में था।
  - जुलाई 2021 में चीन की सात सरकारी एजेंसियों ने संयुक्त रूप से दशिया-नरिदेश पारित किये जिसमें वेतन, कार्यस्थल की सुरक्षा, कामकाज़ का माहौल और वविाद नपिटान सहित क्षेत्रों में खाद्य वतिरण श्रमिकों के अधिकारों की बेहतर सुरक्षा की मांग की गई।
- **भारत में गगि वर्कर्स से संबंधित मुद्दे:**
  - **नौकरी और सामाजिक सुरक्षा का अभाव:** भारत में वभिन्न गगि वर्कर्स श्रम संहिता के दायरे में नहीं आते हैं जिसके चलते उन्हें **स्वास्थ्य बीमा और सेवानिवृत्त योजनाओं जैसे लाभों तक पहुँच प्राप्त नहीं हो पाती है।**
    - इसके अलावा गगि श्रमिकों को अक्सर **चोट या बीमारी की स्थिति में नयिमति/पारंपरिक कर्मचारियों के समान सुरक्षा प्राप्त नहीं होती है।**
  - **डजिटल डविाइड:** गगि इकॉनमी काफी हद तक टेक्नोलॉजी एवं इंटरनेट एक्सेस पर नरिभर करती है, यह उन लोगों के लिये काम में बाधा उत्पन्न करती है जिनके पास इन संसाधनों की उपलब्धता नहीं है परिणामस्वरूप यह आय असमानता को और भी अधिक बढ़ा देती है।
  - **ऑकड़ों की अनुपलब्धता:** भारत में गगि इकॉनमी संबंधी ऑकड़ों एवं इस पर शोध की कमी है जिससे नीति निर्माताओं के लिये इसके आकार, दायरे तथा अर्थव्यवस्था व कार्यबल पर प्रभाव को समझना मुश्किल हो जाता है।
  - **कंपनियों द्वारा शोषण:** भारत में गगि वर्कर्स को अक्सर नयिमति/पारंपरिक कर्मचारियों की तुलना में कम भुगतान किया जाता है और उनके पास समान कानूनी सुरक्षा नहीं होती है।
    - कुछ कंपनियों देयता और करों का भुगतान करने से बचने के लिये गगि कर्मचारियों को स्वतंत्र ठेकेदारों के रूप में गलत वर्गीकृत करके उनका शोषण कर सकती हैं।

## आगे की राह

- **सामाजिक सुरक्षा कवच:** सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि वृद्ध श्रमिकों हेतु वतितीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये गगि श्रमिकों की **पेंशन योजनाओं** एवं स्वास्थ्य बीमा जैसे सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों तक पहुँच हो।
  - साथ ही गगि वर्कर्स को पारंपरिक कर्मचारियों के समान श्रम अधिकार दिये जाने चाहिये, जिसमें यूनियनों को संगठित करने एवं उनके गठन का अधिकार शामिल है।
- **शिक्षा और प्रशिक्षण:** सरकार को गगि वर्कर्स के कौशल में सुधार और उनकी कमाई की क्षमता बढ़ाने के लिये शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नविश करना चाहिये।
- **नषिपक्ष प्रतस्पर्द्धा और नवाचार को प्रोत्साहित करना:** सरकार ऐसे नयिम बनाकर नषिपक्ष प्रतस्पर्द्धा को प्रोत्साहित कर सकती है जो कंपनियों को श्रमिकों को स्वतंत्र ठेकेदारों के रूप में गलत वर्गीकृत करने से रोकते हैं और नषिपक्ष व्यापार प्रथाओं को लागू करते हैं।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, पछिले वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. भारत में महिला सशक्तीकरण की प्रक्रिया में 'गगि इकॉनमी' की भूमिका का परीक्षण कीजिये। (मुख्य परीक्षा- 2021)

### स्रोत: द हद्रि